छोटे छोटे कर्ज से संवरती जिंदगी

ज्योति रानी

ग्रामीण गरीबी को दूर करने में सबसे बड़ी चुनौती है, निर्धनों के स्वमितत्व वाले संशाधनों की कमी. भारत के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त अनुभव से यह पता चला है कि निर्धनों का सशक्त संस्थागत मंच उन्हें अपने लिए मानव, वित्तीय और सामाजिक संसाधन तैयार करने में सक्षम बनाता है. इन संसाधनों से निर्धन समुदाय अपने अधिकार एवं हकदारी प्राप्त कर सकते हैं और सावर्जनिक एवं निजी क्षेत्रों के अवसरों और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. गरीबी को मात देने के लिए जेएसएलपीएस द्वारा झारखंड के ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक घर से महिलाओं को आजीविका सखी मंडल से जोड़ा जा रहा है. जेएसएलपीएस का उद्देश्य वर्ष 2019-20 तक झारखंड के सभी ग्रामीण गरीब परिवारों को आजीविका सखी मंडल से जोड़कर गरीबी से बाहर निकालना है.

गरीबी को पूरा करने वाली विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए, निर्धनों की आत्मनिर्भरता, स्व-प्रभंदित संस्थायों का निर्माण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम का एक मुख्य तत्त्व है. निर्धन महिलाओं को समुदाय आधारित संगठनों (सखी मंडल, ग्राम संगठन, संकुल संगठन) में एकजुट करने के बाद एनआरएलएम कार्यक्रम लाभप्रद आजीविकाएं सृजित करने की दृष्टि से निधियां प्राप्त करने और अपने हुनर और परिसंपतियों का दायरा बढ़ाने में इन संस्थायों की मदद करता है.

आजीविका सखी मंडल से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर रही हैं. अभी तक 17,68,684 महिलाओं ने 5,13,36,24,248 का ऋण लिया है और अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए आजीविका के स्त्रोतों को मजबूत करने में जुटी है.

झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के एमआइएस स्वलेखा के आकड़ों के अनुसार, 38 फीसदी कर्ज के पैसों को आजीविका के स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया है. 32 फीसदी महिलाओं ने कर्ज का पैसा खेती करने में लगाया है, जिसमे उन्होंने श्रीविधि द्वारा खेती की, सब्जी उत्पादन का काम किया और कृषि उपकरण का व्यवसाय किया. तीन फीसदी महिलाओं ने पशुपालन की शुरुआत की और बकरी, सूकर, बत्तख, गाय तथा मछली पालन करके अपनी आय में बढ़ोतरी की. 13 फीसदी महिलायों ने ऋण का उपयोग संपति निर्माण जैसे घर बनाने, घर मरम्मत, जमीन खरीद, दो पहिया वाहन, गहने एवं घर का सामान खरीदने में किया. ऋण का एक छोटा हिस्सा साहुकारों के ऋण अदाएगी में भी इस्तेमाल हुआ है. 24 फीसदी ऋण का हिस्सा, जो कि दूसरा बड़ा हिस्सा है, सामाजिक अवसरों पर खर्च किया गया, जैसे तीज-त्योहार और शादी इत्यादि. इसमें एक अच्छी बात उभरकर यह आयी कि अब ग्रामीण इन खर्चों के लिए साहूकारों के पास नहीं जा रहे हैं और अधिक सूद के चक्रव्यूह में भी नहीं फंस रहे हैं. चौंकाने वाली बात जो सामने आयी है कि कुल ऋण का 16 फीसदी भाग, जो की तीसरी बड़ी राशि है, सेहत पर खर्च हो रहा है. ऋण का सात फीसदी हिस्सा महिलाएं अपने बच्चों की और कुछ महिलाएं खुद की शिक्षा में लगा रही है. वैसे तो यह हिस्सा काफी कम है, पर भी शिक्षा की तरफ एक सराहनीय कदम है. ऋण का दो फीसदी हिस्सा खाद्य सामग्री जुटाने और एक फीसदी अन्य जरूरतों को पूरा करने में खर्च किया गया है. ये आंकड़ें बताते हैं कि कैसे गांव की ग्रामीण महिलाएं सखी मंडल से जुड़कर अपने और परिवार के जीवन को सशक्त, समृद्ध और प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयासरत है. आजीविका सखी मंडल के रूप में महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने का सहारा मिला है. अब उन्हें यह सोचना नहीं पड़ता कि आपत्ति में पैसा कहां से आयेगा? उन्हें समूह से शक्ति मिली है.

सिंगारी आजीविका महिला संकुल संगठन की सदस्याएं.

महिलाओं के लिए आय का साधन है समूह : मैरून बीबी

मैरून बीबी जो कि पोखिगाला ग्राम, बरवाडीह प्रखंड, लातेहार जिले के रहने वाली है. अपनी आपबीती सुनाते हुए कहती हैं कि जब मैं नगीना आजीविका सखी मंडल से जुड़ी, तब मैंने ऋण लेकर सबसे पहले अपने पति की बीमारी के लिए दवाएं खरीदी और कुछ समय बाद जब समूह में चक्रीय और सामुदायिक निधि का पैसा आया, तब मैंने ऋण लेकर मुर्गीपालन की शुरुआत की और इस तरह मुझे एक आय का साधन मिला.

सिलाई सीखतीं युवतियां

कौशल विकास का प्रशिक्षण लेता युवक

दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों के लिए नयी पहल

ग्रामीण महिलाओं के साथ-साथ दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को स्वयं सहायता समूह में जोड़कर जीने का नया आसरा देने के लिए झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी लगातार कार्य कर रही है. इस प्रयास के बल पर दिव्यांग एवं बुजुर्ग अपनी मूलभूत जरूरत को पूरा करते हुए समृद्ध आजीविका की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. इस प्रयास का उद्देश्य समाज के मुख्यधारा से कट चुके दिव्यांग एवं बुजुर्गों को वापस समाज से जोड़ना है. स्वयं सहायता समूह का कार्य अभी झारखंड राज्य के तीन जिलों में शुरू हुआ है, जिसमें रांची, पश्चिम सिंहभूम और पाकुड़ है. वृद्ध स्वयं सहायता समूह तीन प्रकार के हैं- महिला, पुरुष तथा मिश्रित स्वयं सहायता समूह. साल 2016 के अंत तक कुल 390 समूह बने हैं, जिसमें 98 महिला, 130 पुरुष और 162 मिश्रित समूह शामिल है. समूह से जुड़कर वृद्ध महिला एवं पुरुष अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं. राजधानी रांची जिले के नामकुम प्रखंड स्थित सर्वल गांव की एक महिला है ढुमा मुंडा. ढुमा मुंडा को बहुत पहले से चलने में समस्या थी और जरूरत के लिए उनके पास एक जोड़ी चप्पल भी नहीं थी. समूह से जुड़ते ही ढुमा ने 150 रुपये का ऋण लेकर सबसे पहले अपने लिए चप्पल खरीदी और समय के साथ ऋण भी वापस किया. यह तो बस एक शुरुआत है. आगे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण वृद्धों को आजीविका से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की योजना है. वहीं दिव्यांगों के स्वयं सहायता समूह बनाने का काम भी राज्य के तीन जिलों में शुरू किया गया है. इसके पीछे की सोच है समाज के दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराकर आर्थिक एवं सामाजिक मुख्यधारा से भी जोड़ा जा रहा है. रांची, हजारीबाग एवं दुमका के कई प्रखंडों में इस कार्य को शुरू किया गया है, जिसके तहत दिव्यांगों के बेहतरी के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में अभी हाल ही में रांची में दिव्यांगजनों के रोजगार मेला भी आयोजित किया गया था.